POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2017/अंक 07

मासिक प्रेषण दि. 8 जुलाई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जुलाई, 2017 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! देश को आजाद हुए 70 साल होने को आए, लेकिन देश का किसान अभी भी कर्ज के जाल में फंसा है। यह गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि सरकारें किसानों की हितैषी बन कर उनकी भलाई के लिए कई योजनाओं की घोषणा करती रही है।

हर साल अरबों-खरबों रुपए इन योजनाओं के नाम पर खर्च भी किए जाते रहे हैं। लेकिन सही मायने में उनका लाभ किसानों को नहीं मिल पाया। आज भी वे अपनी जमीन-जायदाद गिरवी रखने को मजबूर है। यह ही नहीं, कर्ज से दबे हजारों किसान आत्महत्या जैसे गलत कदम उठाने तक को विवश हो जाते हैं।

हमने देखा, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में कर्ज माफी और अन्य मांगों को लेकर जो किसान आंदोलन हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कई राजनीतिक दल किसानों के हिमायती बन अपनी रोटियां सेंकने में मशगूल हो गए। आंदोलन की चिनगारी अगर पूरे देश में फैल जाती तो हालात और बिगड़ सकते थे।

मेरे खयाल से, किसानों को इन हालातों से उबारने के लिए कर्ज माफी को सही विकल्प नहीं माना जा सकता। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भी कई विकल्प तलाश करने होंगे। इसी वजह से शायद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि कर्ज माफी के बोझ को राज्य सरकारों को अपने स्तर पर झेलना होगा, इसमें केन्द्र कोई मदद नहीं करेगा।

इसमें दो राय नहीं हो सकती कि देश का किसान गंभीर संकट में है और वह खेती से विमुख भी हो सकता है। समय रहते किसानों को इस संकट से उबारने के लिए देश के नीति आयोग को गंभीर चिंतन करना होगा। समय आ गया है कि किसानों को साथ लेकर उनके लिए ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिससे वह सही मायने में अन्नदाता कहला सके।

उत्पाद बेच पल्ला नहीं झाड़ सकेंगी ई-कॉमर्स कंपनियां

उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचने के बाद ई-कॉमर्स कंपनियां यह कह कर पल्ला नहीं झाड़ सकेंगी कि हम तो केवल मार्केट प्लेस हैं, बेचने वाला तो कोई और है। यदि वह ऐसा करेंगी तो उन पर भारी जुर्माना लग सकता है। संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने के लिए तैयार नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं।

नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में सभी उत्पादों पर छह डिक्लेरेशन को बड़े-बड़े अक्षरों में प्रकाशित करने को अनिवार्य कर दिया गया है।

इस कानून में ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने मार्केट प्लेस पर बेचे जाने वाले सभी पेकेज्ड उत्पादों की असली एमआरपी उसकी मात्रा और कंज्यूमर केयर के नंबर को उत्पाद के साथ ही प्रदर्शित करें।

कीमत वेरिफाई नहीं कर पाते ग्राहक

कई ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि ई-कॉमर्स साईट्स पर उत्पादों को भारी डिस्काउंट दिखा कर बेच दिया जाता है। उत्पाद डिलीवर होने पर पता चलता है कि जिसे डिस्काउंट कीमत बताया गया था, वह असल में एमआरपी है। ऑनलाइन खरीदने पर उपभोक्ता उत्पाद की कीमत को वेरिफाई नहीं कर पाता।

सीट नहीं मिली, अब रेलवे देगा मुआवजा

दिल्ली निवासी विजय कुमार ने उपभोक्ता मंच में रेलवे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उन्होंने विशाखापत्तनम से नई दिल्ली आने के लिए सीट आरक्षित करवाई। घुटने के दर्द से परेशान होने की वजह उन्होंने नीचे की बर्थ बुक कराई थी। जब वह विशाखापत्तनम से दक्षिण एक्सप्रेस में सवार होकर नई दिल्ली आ रहे थे तो मध्यप्रदेश के बीना में कुछ लोग कोच में चढ़े और उनकी आरक्षित सीट पर कब्जा कर लिया। उन लोगों ने कोच में मौजूद यात्रियों से भी बदसलूकी की। उन्होंने इसकी टिकट चेकर और रेलवे अधिकारियों से शिकायत करनी चाही तो इन्हें कोई नहीं मिला। रेलवे ने भी उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने रेलवे को सेवा का दोषी माना और विजय कुमार को 75 हजार रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए। विजय कुमार ने मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की जिसे मंच ने ठुकरा दिया। विजय कुमार मामले को दिल्ली उपभोक्ता राज्य आयोग में भी ले गए और मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी की मांग की। लेकिन आयोग ने मुआवजा राशि को सही व तर्क संगत मानते हुए जिला मंच के आदेश को कायम रखा। अब रेलवे को 75 हजार रुपए विजय कुमार को बतौर मुआवजा अदा करने होंगे।

जैविक खेती की ओर वापस लौटना होगा- प्रभुलाल सैनी

हमारे देश की 1960 से पहले जैविक खेती के मामले में पूरी दुनिया में पहचान थी। इसके बाद हरित क्रांति के दौर में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के मकसद से रासायनिक खेती को बढ़ावा दिया गया। इससे देश में खाद्यान्नों की मात्रा में तो बढ़ोतरी हुई लेकिन उसके दुष्परिणाम आज हमें दिखाई दे रहे हैं। इन दुस्परिणामों को रोकने के लिए हमें वापस जैविक खेती की ओर लौटना होगा।

उक्त विचार प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री, राजस्थान ने 'कट्स' द्वारा राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परियोजना प्रो-ओर्गेनिक-द्वितीय के शुभारम्भ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए।

कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष राव राजेन्द्र सिंह ने अपने सम्बोधन में कहा कि जैविक खेती को प्रोत्साहित करने का विचार सराहनीय है। इसके माध्यम से किसान की आय में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। किसानों को इसके लिए अनुदान भी दिया जा सकता है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने देश व विदेश स्तर पर जैविक खेती के आंकड़ों को दर्शाते हुए कहा कि इस परियोजना के माध्यम से सतत विकास को बढ़ाया जाएगा।

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित

'कट्स' द्वारा वर्ष 2002 से हर साल ग्रामीण पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के मकसद से 'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

इस बार वर्ष 2016 के लिए यह पुरस्कार शुभारम्भ समारोह के दौरान मुख्य अतिथि प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किया गया। उन्होंने दैनिक भास्कर के पत्रकार चैतन्य कुमार मीणा को प्रशस्ति पत्र एवं 10 हजार रुपए का चैक प्रदान कर सम्मानित किया।

चैतन्य कुमार मीणा सीकर जिले के अजीतगढ़ के निवासी है। उन्होंने वर्ष 2016 के लिए चयनित विषय 'जल स्वावलंबन अभियान' विषय पर प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक भास्कर में अनेक रोचक एवं तार्किक स्टोरियां प्रकाशित कर आमजन में जागरूकता लाने एवं जनचेतना जागृत करने का काम किया था।

सांसद नहीं बदल पाए गांवों के हालात

सांसद आदर्श ग्राम योजना में प्रधानमंत्री के साथ जन दबाव के चलते सांसद गांवों को गोद तो ले रहें है लेकिन उन गांवों में हालात नहीं बदल रहे हैं। जबकि ग्रामीण विकास की इस महत्वाकांक्षी योजना की निगरानी केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पास है। इसके अलावा राज्यों में मुख्य सचिवों को भी इन गांवों की प्रगति से जोड़ कर रखा गया है।

पिछले दिनों ग्रामीण विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक में यह तथ्य उजागर हुआ है। इसके मुताबिक कई सांसदों व मंत्रियों ने पहले चरण में गोद लिए गांवों के विकास के लिए अभी तक पूरा बजट मुहैया नहीं कराया है। अब तीसरा चरण चल रहा है लेकिन कई सांसद गांव गोद लेने से ही कन्नी काट रहे हैं।

बारिश से पहले निपटें अभियान के काम

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान' के प्रथम चरण के अच्छे नतीजे सामने आने लगे हैं। जल स्वावलंबन से जुड़े क्षेत्रों में टैंकरों से जल सप्लाई में 57 प्रतिशत की कमी आई है।

गैर-मरुस्थलीय 23 जिलों के संबंधित क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ गया है। मांडलगढ़ के 265 सूखे कुंओं में फिर से पानी आ गया है। पहले चरण में बनाए गए 96 हजार ढांचों में पानी आया था। अभियान की राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना हुई है। उन्होंने कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस में अभियान के दूसरे चरण के कामों को भी बारिश से पहले पूरा करने को कहा है।

प्रदेश में पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट

राजस्थान के 32 फीसदी लोगों ने माना है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार राज्य में पुलिस विभाग में है। इस बात का खुलासा सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की हालिया सर्वे रिपोर्ट 'इंडिया करप्शन स्टडी' में किया गया है।

सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 43 फीसदी लोगों का मानना है कि एक साल में प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। वहीं 32 फीसदी लोगों का कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार कम हुआ है। जबकि प्रदेश के 25 फीसदी लोगों ने माना है कि भ्रष्टाचार न घटा है और न ही बढ़ा है।

किसान बेहाल..कंपनियां मालामाल

देश के किसान कर्ज में डूबे हैं। लेकिन कृषि सेक्टर से जुड़ी कंपनियों की कमाई बढ़ती जा रही है। कंपनियों के स्टॉक्स बीते एक साल में 16 से 76 फीसदी तक बढ़े हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी है जो पूरी तरह किसानों पर ही निर्भर हैं और वे किसानों के दम पर करोड़ों रुपए कमा रही हैं।

खाद का उत्पादन करने वाली कंपनियां, बीज और फसलों की सुरक्षा के उपाय बताने वाली कंपनियां, फल व सब्जी के बीज तैयार करने वाली जैसी कई कंपनियों की आय में काफी वृद्धि हुई है जबकि देश के 59 फीसदी किसान अपनी फसल को कम दामों में बेचने को विवश हैं।

मनरेगा में साढ़े छह लाख काम अधूरे

प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) सिर्फ करोड़ों रुपए की स्वीकृतियां जारी करने की गारंटी दे रही है। हाल यह है कि न रोजगार की गारंटी है और न ही स्वीकृत काम पूरा करने की। प्रदेश में साढ़े छह लाख काम बरसों से अधूरे पड़े हैं।

अधिकारी हर साल उन्हें प्रगतिगत बताकर फाइलें दौड़ा रहे हैं लेकिन यह सिर्फ कागजी कार्यवाही बनकर रह जाते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मनरेगा पर सबसे ज्यादा फोकस होने के बावजूद वहां सबसे ज्यादा काम अधूरे हैं। बांसवाड़ा में कुल स्वीकृत कामों का महज 36.6 फीसदी व डूंगरपुर में 40.73 फीसदी ही काम पूरे हुए हैं।

असफल रही गरीब कल्याण योजना

कालेधन को लेकर बनाई गई केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पूरी तरह असफल रही है। सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कालेधन का खुलासा करने वाली यह योजना फ्लाप साबित हुई है। राजस्व विभाग के अनुसार योजना में करीब 5 हजार करोड़ रुपए का ही खुलासा हुआ है।

योजना की घोषणा होने से पहले ही कई लोगों द्वारा अपनी नकदी विभिन्न खातों में जमा करना इसकी वजह माना जा रहा है। दूसरा कारण योजना के तहत कर की दर और जुर्माना था।

गांव ने कायम की अनूठी मिसाल

प्रदेश के राजसमंद जिले के पीपलान्त्री गांव में हर बेटी के जन्म पर 111 फलदार पेड़ लगाए जाते हैं। इन पेड़ों की सुरक्षा का बीड़ा भी गांव वाले ही मिलकर उठाते हैं। दीमक आदि से बचाव के लिए वे पेड़ों के चारों ओर एलोवेरा के पौधे भी लगाते हैं।

इसके अलावा गांव के निवासी मिलकर 21 हजार रुपए व बच्ची के माता-पिता 10 हजार रुपए कुल 31 हजार रुपए की बिटिया के लिए बैंक में 20 साल के लिए एफ.डी. भी करवाते हैं। बिटिया के माता-पिता इस बात का लिखित में हलफनामा भी देते हैं कि वे अपनी बेटी को उचित शिक्षा दिलवाएंगे और कानूनी उम्र होने पर ही उसका विवाह करेंगे।

गांव में लगाए गए पेड़ और एलोवेरा के पौधे गांव के निवासियों के लिए उनकी जीविका का साधन बन गए हैं। देश के अन्य गांवों के लिए यह मिसाल प्रेरणा दायक है।

राजस्थान को बनाएं हरा-भरा प्रदेश

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेशवासियों से राजस्थान को स्वच्छ व हरा-भरा प्रदेश बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। राजे न कहा कि प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखकर ही हम आने वाली पीढ़ी को सुखद व सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के पहले चरण में सभी के सहयोग से पूरे प्रदेश में 28 लाख से भी ज्यादा पौधे लगाए गए थे। दूसरे चरण में भी जन सहयोग से लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर